

THE PILLARS OF DEMOCRACY

VOLUME-4 ISSUE-7 JULY 2024 AMBERNATH PAGE 1 OF 4 RS 5/-

न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका तथा मीडिया का लेखा-जोखा जनता तक पहुंचाना , प्रारंभ मे एक मासिक के रूप में शुरू, इस मासिक समाचार पत्र का मूल उद्देश्य है । पाठक अपना विचार हिन्दी या अंग्रेजी में बेहिचक दे सकते हैं । शर्त सिर्फ यह है कि विचार किसी भी तरह के , प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से,पूर्वाग्रह से रहित होना चाहिए ।
email id: vote1957@gmail.com

काला दिवस
पश्चिम बंगाल बार काउंसिल ने तीन अपराधिक कानूनों के खिलाफ 1 जुलाई 2024 को काला दिन के रूप में मनाने का फैसला लिया है।
जातव्य है कि भारत सरकार ने तीन पुराने अपराधिक कानूनों Indian Penal Code , Criminal Procedure Code तथा Indian Evidence Act को बदल कर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया है।
इन तीनों कानूनों को तीन दिन बाद 1 जुलाई से लागू किया जाना है।बहुत सारे न्यायविद इन कानूनों को अनावश्यक बताया है। कुछ सुधारों को खतरनाक बताया है। पश्चिम बंगाल बार काउंसिल ने इन नए कानूनों को अलोकतांत्रिक तथा खतरनाक बताया है।

ईडी सीबीआई में प्रतिस्पर्धा
"ताड़ से गिरे खजूर में अटके" जेल में बंद केजरीवाल पर लागू होती है। ईडी के मामले से राहत मिलने के आसार प्रबल दिखने लगे तब सीबीआई ने जोर पकड़ा और केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया तथा जज साहब ने कस्टडी भी दे दी।सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल ने बदलती परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। बाद में याचिका में उचित सुधार कर याचिका दायर कर सकते हैं।

सोनाक्षी सिन्हा -जहीर इकबाल
अटकलें और अफवाहों को विराम लग गया। दोनों अब पति पत्नी हैं।
भारत में कुछ अरसे से बनाए जा रहे सामाजिक माहौल के मददेनजर इन दोनों की शादी क्रांतिकारी ही हो सकती है तथा दोनों के हौसलों की दाद देनी होगी !

राम जी के अयोध्या में भी बीजेपी हारी
अयोध्या से भी बीजेपी का हार जाना आश्चर्य जनक है। वहीं अयोध्या जहां इसी साल जनवरी में प्रधानमंत्री ने बड़े धूमधाम से राममंदिर में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की थी। ये भी दावा किया जाता है कि अयोध्या में सड़कें बनी हैं एयरपोर्ट बना है। पर वहां के लोगों ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को च्ना है।

तीन आपराधिक कानून नहीं रहे !
आज से संसद द्वारा पारित अपराधिक कानूनों के नए अवतार लागू हो रहे हैं। इनके नए अवतारों में इनके नए नाम ही विशेष हैं जो हिंदी में हैं , विषय वस्तु (content) करीब करीब वही पुरानी हैं। धाराओं के क्रम में बदलाव हैं। मशहूर दफा 302 तथा 420 बदल गए हैं। कोई भी बदलाव ऐसा नहीं है जिससे लगे कि इन कानूनों में , दिखाने के लिए ही सही, किसी भी तरह के आमूल चोल परिवर्तन की जरूरत थी।
हां, जो थोड़े कुछ बदलाव हैं वे वांछनीय भी हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे गए संदेशों को भी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
पर आतंकवादी संबंधित विशेष कानूनों की बातों को आईपीसी में शामिल करना इसके प्रयोग पर सवाल पैदा करते हैं।
पुराने तथा नए कानून निम्न हैं:-
Indian Penal Code - भारतीय न्याय संहिता, Criminal Procedure Code - भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,Indian Evidence Act - भारतीय साक्ष्य अधिनियम

Congratulations
To Shri Narendra Modi for assuming the charge of Prime Minsiter for the record third consecutive term at par with the first Prime Minister of India Pt Jawahar Lal Nehru.
However the fractured mandate this election is clearly a brake on the hitherto arbitrary functioning of the Executive or the Parliament. He will have to take every body into confidence

राम तेरी गंगा मैली हो गई !
"नमामि गंगे" तथा "राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (National Mission for Clean Ganga)" की धज्जियां उड़ते देखना है तो गंगा तट पर बसे बिहार के बक्सर शहर के रामरेखा घाट या चरीतर वन श्मशान भूमि को देख लीजिए।
गंदगी सरेआम है। रामरेखा घाट पर बने लोगों के लिए बने शेड से एकदम सटकर गंदगी या कूड़े का ढेर लगा हुआ है। ऐसा लगता है कि हफ्तों किसी ने सफाई नहीं की है। लोग खुलेआम मूत्र त्याग करते दिख जायेंगे क्योंकि आसपास कोई शौचालय नहीं है।
अश्विनी कुमार चौबे जैसे जानेमाने लोग यहां के सांसद रह चुके हैं। हालांकि इस बार के आम चुनाव में उन्हें यहां से चुनाव लड़ने का टिकट नहीं मिला था और सीट आरजेडी के उम्मीदवार ने जीती है।

Who Is The Winner !
This is the first time in the history wherein a winning party has to go on repeatedly convincing the people that they have own ! This itself is pitiable.
What happened to the double engine driven State of Uttar Pradesh where both the great men of BJP ie Modi ji and Yogi ji could not save UP from the INDIA Sunami which has virtually swept the UP. Even Ayodhya where this party has been doing drama consistently could not save its face.
Even Maharashtra where a big drama had been staged by engineering defections in ShivSena and NCP - the MVA (Maha Vikas Aghadi) has performed well and BJP has been reduced to a single digit number of 9 from its 2019 tally of 23.
In West Bengal TMC(Trinamool Congress) has not only checkmated BJP but also has been able to bring it down to 12 from 18 in 2019.
Yes, BJP did have windfall from Andhra Pradesh and Bihar where its allies TDP (Telugu Desam Party) and JDU(Janata Dal United) with 16 and 12 seats representing a big chunk amongst the combined seats of the so-Called almost forgotten NDA which can be said to have become almost defunct.

ये कैसा न्याय है , भाई !
दिल्ली की एक अदालत ने आज वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को एक मानहानि के मामले में 5 महीने की सजा तथा 10 लाख रुपए क्षतिपूर्ति का दंड दिया है। ये सजा 23 साल पुराने मामले में सुनाई गई है। दिल्ली के मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर वी के सक्सेना द्वारा 2001 में जब वे गुजरात में एक एनजीओ चलाते थे। उन्हें मेधा पाटकर ने देशभक्त नहीं डरपोक (coward) कहा था। इसी बयान के खिलाफ सक्सेना ने 2001 में मानहानि का मामला दायर किया था गुजरात के एक कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दिल्ली के एक कोर्ट में 2003 में स्थानांतरित किया गया था।

Elon Musk Rakes Up Debate On Use Of EVM in India
Results of just held Lok Sabha elections had almost silenced the critics of EVMs which had been the hot topic for debates hitherto and issue has gone upto our Supreme Court as well.
As the acrimony over the use of EVM in elections was settling down to rest - the owner of the Tesla company and the Twitter(now X) has by his tweets stirred the debate on EVM once again in India,
Elon Musk has said, "We should eliminate electronic voting machines. The risk of being hacked by humans or AI, while small, is still too high."
The developed countries like USA, England France, Germany, Neitherland don't use EVMs in their elections. This gives strength to the critics of EVMs.
Though electronic machines are useful for giving results fast when we compare it with the manual paper ballots which entails delay in voting and counting ----- yet, is it not worth to have consensus among all the political parties over discarding EVM and switching over to the hitherto Paper Ballot System !
BJP should come out of its obsession with the EVMs. After all integrity of the system must be beyond doubt !

THE PILLARS OF DEMOCRACY

VOLUME-4 ISSUE-7 JULY 2024 AMBERNATH PAGE 2 OF 4 RS 5/-

इतिहास मिटाने की मनमानी

एनसीईआरटी ने 12 कक्षा के राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम से बाबरी मस्जिद से जुड़े कुछ अध्यायों में काट छांट कर पुस्तक प्रकाशित की है। इससे खफा दो बुद्धिजीवियों ने जो एनसीईआरटी के पूर्व मुख्य सलाहकार सुहास पाल्शीकर तथा योगेंद्र यादव ने एनसीईआरटी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। इनका कहना है कि इन लोगों द्वारा पाठ्यक्रम में किसी तरह की काट छांट से असहमति जताई गई है। इसके बावजूद पुस्तक में बतौर सलाहकार उनके नाम लिखे गए हैं।

पाठ्यक्रम में किए गए बदलाव निम्न हैं:-

1. पुस्तक में "बाबरी मस्जिद" की जगह "तीन गुम्बद वाला ढांचा" लिखा गया है।
2. गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक बीजेपी का रथ यात्रा तथा कारसेवकों की भूमिका को नहीं दर्शाया गया है।
3. बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद हुए साम्प्रदायिक दंगों का जिक्र नहीं है।
4. बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद बीजेपी शासित सभी सभी राज्यों में राष्ट्रपति लगाए जाने वाली बात का भी जिक्र नहीं है।
5. बीजेपी द्वारा अयोध्या के बाबरी मस्जिद गिराए जाने की घटना पर बीजेपी द्वारा व्यक्त किए गए खेद का भी कोई जिक्र नहीं है।

मूल पाठ्यक्रम में और भी बदलाव किए गए हैं।

बीजेपी के कार्यकाल की यह भी एक खासियत रही है कि सड़कों, रेल स्टेशनों के नामों के साथ साथ इतिहास बदलने का भी काम किया है। किताबों की विषय वस्तुओं में हेराफेरी की बात भी अक्सर सुनने को मिलती है।

इतिहास बीते हुए काल का रिकॉर्ड होता है। इसे जहांतक संभव हो घटनाओं का ज्यों का त्यों विवरण होना चाहिए। हां, इसका भी ध्यान जरूर रखना चाहिए कि इन पाठ्यक्रमों से आने वाली पीढ़ियों में कटुता या उन्माद नहीं पनपे या बढ़े !

NEET Must Be Neat

In India Paper leaks and other malpractices in examinations are not new. Coaching classes are alleged to have roles in these malpractices. But never ever the hue and cry has been as acrimonious as is being witnessed in regards to the NEET (National Eligibility cum Entrance Test) conducted this year. Media is seen as unusually highlighting the issue.

For paper leak government side is in denial mode. Petitions have been filed in the Supreme Court,

It is necessary to dispel the cloud of suspicion shrouding the fairness of conduct of the NEET which is conducted every year to select the students for admission to MBBS and BDS courses.

One way to do this is that Government should appoint a high power committee to look into the issues and take appropriate steps to instill and restore credibility in the system.

And if there has really been paper leaks it is better to conduct re-test and the sooner it is done the better it would be for the students and the people of India !

How, Now, Our Constitution Is Safe !

BJP supporters are not able to digest the humiliation suffered by BJP at the hands of the Congress and the India Alliance whose performance was par excellence given the onslaught perpetrated and unleashed or let loose by the investigating agencies virtually on all opposition leaders. India Alliance never claimed any better result than what they have got, Take this in contrast with what the BJP with its oft repeated slogan of 400 paar goti!It is 240 and 293 which the NDA could get.

Congress and India are happy that they have checked the hate mongering, undemocratic and unconstitutional actions which were being aggressively followed by the govt under Modi ji. He is not as free as he was. He does not have even simple majority to push through the bills to make laws as he did with 3 farms laws and other legislations.

>>>

गुत्थी

मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा संसदीय क्षेत्र का चुनाव परिणाम शुरू से ही कौतूहल का विषय बना हुआ है। कारण ये है कि यहां हार /जीत सिर्फ 48 वोटों के मार्जिन से हुई है। यह क्षेत्र भारत में शायद पहला क्षेत्र है जहां इतने कम मार्जिन से किसी की जीत हुई हो।

तिस पर ये नई खबर कि गिनती केंद्र (Counting Centre) में जीतने वाले उम्मीदवार के सहायक के पास उस केंद्र के चुनाव आयोग के कर्मों का मोबाइल फोन देखने को मिला। ऐसा आपत्तिजनक है क्योंकि गिनती केंद्र के अंदर किसी को भी मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं । एफआईआर दर्ज हुआ है। पुलिस जांच कर रही है। आगे भी कोर्ट कचहरी होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। चुनाव कर्मों को निलंबित कर दिया गया है।

हैं न ये गुत्थी ! क्या ये गुत्थी सर्वमान्य ढंग से सुलझ पाएगी। मुझे तो नहीं लगता है । हां, ईवीएम की आलोचना के लिए ऐसी बातें हवा देने का काम जरूर करती हैं।

हारने तथा जीतने वाले दोनों उम्मीदवार पहले के शिवसेना के हैं - हारने वाले उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) से है तथा जीतने वाले उम्मीदवार रविंद्र वायकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना से !

यह कैसा न्याय है, भाई !

तथाकथित भड़काऊ बयान के 14 साल बाद मशहूर लेखिका तथा सक्रिय कार्यकर्ता अरुंधती राय के खिलाफ खतरनाक कानून यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की स्वीकृति दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर दी है।

इतने अर्से के बाद किसी व्यक्ति के खिलाफ अपराधिक प्रक्रिया शुरू करना ही सरकार की मनसा स्पष्ट करता है। वैचारिक अभिव्यक्ति पर इस तरह के अंकुश उचित नहीं है ।

अरुंधति राय द्वारा दिए गए तथाकथित भड़काऊ बयान के लिए ऐसा किया जा रहा है। पर प्रक्रिया में इस विलंब को कैसे उचित ठहराया जा सकता है।

इतिहासपुरुष नीतीश कुमार

नीतीश कुमार इतिहासपुरुष जरूर हैं।इतिहास में इनके विशेष चरित्र के लिए इनको विशेष स्थान जरूर मिलेगा।

इनके जैसा पात्र कहीं भी तथा कभी भी नहीं देखा गया है। बार बार पलटी मारने का इनका विलक्षण तरीका विरले ही देखने को मिलेगा।

भारत में सभी विपक्षी पार्टियों को एक करने का सूत्रधार होना तथा भारत में व्यक्तिगत रूप से सभी नेताओं से मिल कर उनको एक टेबल पर लाना, बाद में अकारण स्वयं अलग हो जाना तथा दूसरे पक्ष में सहर्ष शामिल हो जाना सिद्धांत विहीनता नहीं है तो क्या है !

इन सारी बुराइयों के साथ नीतीश कुमार की सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि व्यक्तिगत रूप से इनकी छवि भ्रष्टाचार से मुक्त तथा साफ सुथरी मानी जाती है तथा कोई भी इनके खिलाफ अबतक उंगली नहीं उठा पाया है भ्रष्टाचार को लेकर।

इसके बावजूद सिद्धांतहीनता ठीक बात नहीं है। वैसे भारत के दलबदलू नेताओं की सिद्धांतहीनता प्रचुर तथा जगजाहिर है।फर्क सिर्फ इतना है कि नीतीश कुमार ने इस माने में अबतक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं तथा सबसे आगे हैं !

To make constitutional amendment 2/3rd majority is required. This neither BJP had nor its NDA has. As such the Constitution is safe. 2/3Rd of 543 comes to 362 MPS whereas NDA in all has 293 only.

Otherwise also Congress has improved its performance and seat score from its previous tally of 44 or so to 99 , nearly double to what it had earlier.

THE PILLARS OF DEMOCRACY

VOLUME-4 ISSUE-7 JULY 2024 AMBERNATH PAGE 3 OF 4 RS 5/-

अतिसंवेदनशील शेयर बाजार

यह बाजार उछाल मारता है , लुढ़कता है , कभी छलांग लगाता है कभी मुंह के बल सीधे नीचे गिर जाता है ! कभी बमबम करता है !कभी भयंकर गिरावट ! तो कभी शानदार रिकवरी !

इस बाजार का स्थिर रहना या सामान्य रहना शायद अच्छी बात नहीं मानी जाती है।

1 तारीख को लोकसभा के एक्जिट पोल के बाद यह बाजार खुशी से उछल उठा। पता नहीं कितना ऊपर चढ़ गया। ऐसा होना शायद अच्छा माना जाता है !

4 जून को लोकसभा का असली रिजल्ट सुनकर शेयर बाजार में सुनामी आ गया। शेयर लुढ़कने लगे।

मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन रही है जानकर इस नाजुक तथा अतिसंवेदनशील बाजार को शायद तसल्ली हुई और अब शायद इस बाजार की धड़कन स्थिर हुई है ।

क्या शेयर बाजार का हलचल स्वाभाविक है या जानबूझ कर इसमें कृत्रिम अस्थिरता पैदा की जाती है।

यदि शेयर मार्केट की अस्थिरता देश की अर्थ व्यवस्था के लिए जरूरी है तब तो उथल पुथल ठीक है। वरना इस पर नियंत्रण क्यों नहीं किया जाता है।

हर्षद मेहता तथा केतन पारिख विगत के दो नाम हैं जिन्हें शेयर बाजार में गड़बड़ी करवाने के लिए जाना जाता है।

मेरी समझ से सेबी (Security Exchange Board of India) अगर चाहे तो शेयर बाजार की सेहत को ठीक रख सकती है। जब कभी अचानक तथा असाधारण उतार चढ़ाव दिखे तो जांच करना चाहिए। शेयर धारकों में विश्वास तथा गारंटी देनी चाहिए कि सरकार बदलने से उनको कोई नुकसान नहीं होगा !

BSP Has Potential To Play Spoilsport

Mayawati 's BSP (Bahujan Samaj Party) is virtually a party with pan-India presence. It had put up its candidates from almost all the seats of all the States but it has drawn blanks and none of its candidates could win any seat.

Had some understanding reached between this party and India Alliance in having seats sharing , at least, in UP - the picture could have been still more spectacular with India Alliance winning 19 more seats in UP. Adding this figure to 44 seats (which the India Alliance has already won in UP) the total tally in UP could have gone upto 63 or even more.

Screenshots (taken from the website of the Election Commission of India) attached herewith this post are of the details of the seats where INDIA Constituents (SP and Congress) have lost the elections and BJP candidates have won. If the votes gained by BSP candidates are simply added to votes gained by India Alliance candidates the total gets far more than the votes gained by the winning BJP candidates.

Differences are bound to be among different political parties but they should develop the spirit of joining together to give fight in case of exigencies to realise the common goals.

हार

भारत की प्रबुद्ध जनता सचमुच धन्यवाद की पात्र है।ये सबका औकात बता देती है। अहंकार तोड़ देती है। बीजेपी के समर्थकों के सर से *"400 पार"* का भूत अभी भी उतरा नहीं लगता है। बीजेपी का 303 सीट से 240 पर आ जाने का भी इन्हें कोई अफसोस नहीं दिखता है। एक्जिट पोल एकदम फ्लॉप साबित हुए हैं।मोदी मोदी करते करते ये लोग बीजेपी का नाम भी लेना भूल गए थे। अब इस चुनाव के झटके के बाद एनडीए पुनर्जीवित हो गया है। एनडीए के सीट भी पहले के 353 से 292 तक आ गए हैं।

इसके बावजूद बीजेपी के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा दिखता है। गाजे बाजे तथा अबीर गुलाल के साथ खुशी मनाते दिख रहे थे। >>>

थप्पड़

आप नेता स्वाति मालीवाल को आप नेता तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर सबकी मौजूदगी में थप्पड़ मारने की घटना घटी ।उत्तरपूर्व दिल्ली से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार को उनके ही संसदीय क्षेत्र में किसी ने थप्पड़ मारा।

और अब अभी अभी नवनिर्वाचित सांसद कंगना राणावत को सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह चंडीगढ़ एयरपोर्ट में वही सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के एक महिला कांस्टेबल ने थप्पड़ मारा है।

स्वाति मालीवाल तथा कंगना राणावत के मामले को तो मीडिया ने खूब उछाला पर कन्हैया कुमार पर कोई भी न्यूज बाइट मुझे तो नहीं दिखा। यह आम सहमति की बात है कि किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करना चाहिए ।

पर ये भी सच है कि कंगना मुंहफट हैं। इनके जैसे और भी बहुत नेता अभिनेता हैं। हमारी बातों का दूसरों की भावना पर क्या असर होता है इसका भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए बोलने से पहले।

सीआईएसएफ की कांस्टेबल का यह कृत्य पूर्व नियोजित नहीं लगता है। ऐसा तत्क्षण भवावेश में किया गया लगता है।(This seems to have been done on the spur of the moment).

किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए लोग तरह तरह के लांछन लगा रहे थे उस वक्त अक्सर बीजेपी के समर्थक - यथा आतंकवादी, देश द्रोही , गद्दार और पता नहीं क्या क्या ! ऐसा ये लोग अभी भी कहते हैं सरकार का विरोध करने वालों को।

उस कांस्टेबल के मुताबिक उसकी मां भी किसानों के आंदोलन में धरने पर बैठती थीं। कंगना राणावत के उस वक्त के बयान ने कि "ये महिलाएं सौ सौ रुपए लेकर आई है " जरूर उस मां की बेटी अर्थात इस कांस्टेबल को जरूर आहत किया होगा।

कुछ भी हो, मामले की जड़ में कोई नहीं जाता है। हिंसा करने वालों को सजा दी जाती है क्योंकि हर अपराधी अपने किए को उचित ठहराता है। पर मेरा मानना है कि जड़ को सींचने तथा पत्तों को काटने या छांटने से क्षणिक राहत जरूर मिल सकती है पर स्थाई राहत के लिए जड़ को नजरंदाज करना उचित रास्ता नहीं हो सकता है।

पर बीजेपी के लोग हार नहीं मानते हैं। वाजपेई जी की कविता *"हार नहीं मानूंगा"* वाली कविता को ये चरितार्थ करते हैं। इसके विपरीत पूरी तरह से मतभेदों से परिपूर्ण पार्टियों द्वारा बनाया गया *"इंडिया एलायंस* ने कम समय में ही इस चुनाव में काफी जोरदार टक्कर दिया है बीजेपी को तथा विश्वगुरु या विष्णु अवतार या 56" जैसे विशेषणों से नवाजे जाने वाले मोदी जी के अश्वमेध घोड़े को रोकने का काम किया है।

- लोकसभा चुनाव में जनता ने अपनी अंतरात्मा का प्रयोग करते हुए :-
1. भारत की पहचान, भारत के लोकतंत्र तथा भारत के संविधान को बचा लिया।
 2. महाराष्ट्र में शिवसेना तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को छिन्न भिन्न करने के प्रयास को पसंद नहीं किया।
 3. यूपी में बुलडोजर की संस्कृति को पसंद नहीं किया।
 4. हिंदू मुस्लिम करने की चाल को पसंद नहीं किया।
 5. 5 किलो चावल के लाभ के लोभ को ठुकरा दिया।
 6. रामजी के मायाजाल में नहीं उलझी।
 7. नफरती भाषणों को पसंद नहीं किया।
 8. विरोध तथा विरोधियों की आवाज दबाने की बात नहीं मानी।
 9. जांच एजेंसियों के कहर से नहीं डरी।
 10. ढोंग और आडंबर को पसंद नहीं किया।

मोदी जी का नारा *"सबका साथ, सबका विश्वास तथा सबका प्रयास"* बहुत उद्देश्यपूर्ण है बशर्ते ये शब्दों में ही नहीं, भाषणों में ही नहीं, अपितु सच्चे मन से व्यवहार में भी प्रयुक्त हों।

THE PILLARS OF DEMOCRACY

VOLUME-4 ISSUE-7 JULY 2024 AMBERNATH PAGE 4 OF 4 RS 5/-

Miscellaneous

Sanjay Singh AAP Neta Tweets

अग्निवीर योजना भारत माँ की सुरक्षा और देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है। ये योजना भारतीय सेना को कमज़ोर करने की योजना है। इसपर पुनर्विचार करके इसको खत्म करना चाहिए।

Rahul Gandhi Tweets

नरेंद्र मोदी 10 वर्षों से 'भय का राज' चला रहे हैं! सभी एजेंसियों, संस्थाओं और मीडिया पर कब्ज़ा कर समाज के हर वर्ग में भाजपा ने सिर्फ डर फैलाने का काम किया है। - किसानों को काले कानूनों का डर - स्टूडेंट्स को पेपर लीक का डर - युवाओं को बेरोज़गारी का डर - छोटे व्यापारियों को गलत GST, नोटबंदी और छापों का डर - देशभक्तों को अग्निवीर जैसी योजनाओं का डर - मणिपुर के लोगों को सिविल वॉर का डर इसीलिये देश की जनता ने 'डर के पैकेज' के खिलाफ जनादेश देकर भाजपा से बहुमत छीन लिया है। डरना-डराना, भय फैलाना भारत की आत्मा के खिलाफ है। हमारे सभी धर्म भी यही सिखाते हैं - डरो मत, डराओ मत। विपक्ष के नेता के रूप में मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं अपनी निजी आकांक्षाओं और विचारों से पहले INDIA की संयुक्त आवाज़ को सदन के समक्ष रखूँ। और सरकार से हमारी यही अपेक्षा है कि वह विपक्ष को दुश्मन नहीं, सहयोगी मान कर देश हित में सबको साथ लेकर काम करे। जय हिन्द।

हिंदुस्तान डर का देश नहीं है। हमारे सभी महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। नरेंद्र मोदी, भाजपा और RSS पूरा हिंदू समाज नहीं हैं- जो हिंसा और नफ़रत फैलाता है, वो हिंदू हो ही नहीं सकता

Editors Guild of India tweets

EGI has written to the Speaker of Lok Sabha, [@ombirlakota](#), and Chairman of Rajya Sabha, Sh Jagdeep Dhankhar, [@RajyaSabha](#), urging removal of access restrictions on journalists from reporting on House proceedings.

Rajdeep Sardesai the Senior ournalist tweets

When he took over exactly 2 years ago, bets were being taken on how long the government would last. Well, he's more than survived and now will probably be the face of the 3 party ruling alliance when Maharashtra goes to the polls later this year. Will be a decisive election that will settle the future of many a neta/party.

Ravish Kumar tweets

न्यूयार्क में Evan Osnos ने लिखा है कि अमरीका में टीवी पर प्रेसिडेंशियल डिबेट की शुरुआत 1960 में हुई थी। उस समय डेमोक्रेट पार्टी से उप राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे। रिपब्लिकन से जॉन एफ़ कैनेडी। वाशिंगटन के NBC चैनल के स्टुडियो में निक्सन और कैनेडी के बीच डिबेट हुई थी। डिबेट से पहले निक्सन सर्वे में आगे चल रहे थे।मामूली बढ़त हासिल थी। डिबेट के बाद कैनेडी मामूली अंतर से राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत गए। डिबेट से पहले कैनेडी ने कई दिन लगाकर तैयारी की थी। बकायदा इंडेक्स कार्ड बनाया और सारे तथ्यों को ठीक से याद कर लिया। कैनेडी ने अपनी तैयारी से निक्सन को हरा दिया। इतिहासकार डोरिस केयर्न्स (doris Kearns) ने अपनी किताब An unfinished Love story : A Personal History of the 19060's में यह सब लिखा है। 2020 में जब बाइडन और ट्रंप के बीच डिबेट हुआ तब स्टुडियो में गेस्ट भी थे। इस बार नहीं थे केवल दोनों थे। ट्रंप 78 के हैं और बाइसन 81 के हैं। उम्र में खास अंतर नहीं है। बाइडन और ट्रंप के डिबेट को लेकर यू ट्यूब से लेकर अखबारों में आपको कई विश्लेषण मिल जाएंगे। देख सकते हैं। मैंने देखा नहीं और पढ़ा नहीं। देखूंगा और पढ़ूंगा जरूर। 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को डिबेट के लिए चुनौती देते रहे मगर उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अमरीका में डिबेट की परंपरा टीवी से शुरू नहीं होती है। कई सदी पुरानी है। 4 जुलाई 1776 को अमरीका आज़ाद हुआ था। उसके बहुत पहले से वहां डिबेट आंदोलन का रूप ले चुका था। इसे LYCEUM MOVEMENT कहते हैं। आज भी LYCEUM HALL आपको दिख जाते हैं। न्यूयार्क में जहां ब्राड-वे है वहां मुझे किसी हॉल के आगे LYCEUM लिखा दिखा था। 1885 में लिंकन और डगलस के बीच जब डिबेट होती थी तो कई घंटों तक चलती थी। दोनों अपना भाषण लिख कर लाते थे और लिखा हुआ भाषण पढ़ते थे। डिबेट लंबी हो जाती थी तो ब्रेक होता था और लोग घर चले जाते थे। डिनर के बाद फिर लौट कर आते थे और डिबेट होती थी। उस दौर में हालत यह थी कि डिबेट के लिए हॉल खाली नहीं मिलता था। यू ट्यूब पर राधा वल्लभ त्रिपाठी बनारस में हुए एक ऐसे ही डिबेट का शानदार उल्लेख करते हैं। राधावल्लभ जी बताते हैं कि 19 वीं सदी में दयानंद सरस्वती शास्त्रार्थ का पुनर्जागरण करते हैं। उन्होंने बहस की शर्तें विकसित की। श्रोताओं की संख्या,स्थान, वक्ताओं के नाम और संख्या पहले से तय हो। पूरी बहस लिखी जाएगी और डिबेट के बाद दोनों पक्ष हस्ताक्षर करेंगे कि हम पराजित हुए या विजित हुए।दयानंद सरस्वती बकायदा अपने खर्च से पोस्टर छपवाते थे और लगाते थे। उनका विज्ञापन पांच भाषाओं में होता था। संस्कृत, अंग्रेजी हिन्दी गुजराती और मराठी में। काशी का शास्त्रार्थ संस्कृत में हुआ था। 16 नवंबर 1869 के दिन काशी के आनंदबाग में दयानंद और पंडितों के बीच शास्त्रार्थ होता है। मूर्ति पूजा के विरोधी थे दयानंद सरस्वती।